दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 11 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 220

महत्वपूर्ण एवं खास

पीएम मोदी ने सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर दी बधाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने अन्य नेताओं को भी मंत्री पदकी शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, हिमंत बिस्वासरमाजी और आज शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को बधाई देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह टीम असम में विकास की यात्रा को और तेज करने तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेगी। श्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे महत्वपूर्ण सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी ने पिछले पांच वर्ष एक जन समर्थक और विकास समर्थक प्रशासन का नेतृत्व किया।असम की प्रगति और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है।

सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर के लिए किया टोल-फ्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में जारी दूसरी कोरोना लहर से निपटने के इंतजामों में भी रफ्तार आ गई है। एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को टोल फ्री कर दिया है। इन वाहनों को एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों जैसा माना जाएगा। देश में कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को दो महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक एंबुलेंस जैसी अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह ही माना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के टोल प्लाजा पर इन टैंकरों की टोल मुक्त आवाजाही का आदेश दिया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर मेडिकल ऑक्सीजन का आवागमन तीव्र गति से सुनिश्चित हो सकेगा।

राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अधीर ने किया संसद सत्र बुलाने का अनुरोध

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के हालात पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए। चौधरी ने पत्र में कहा कि संसद का सत्र बुलाना जरूरी है ताकि कोरोना वायरस से परेशान लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का रास्ता ढूंढा जा सके। उन्होंने देश में कोरोना महामारी के हालात के गंभीर होने का दावा किया और कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय समाधान तलाशने की जरूरत है। गत शुक्रवार को हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी यह कहा गया था कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और पार्टी के कुछ अन्य नेता भी संसद का आपात सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं।

गंगा नदी में बहते मिले 10 शव

बक्सर (आरएनएस)। गंगा नदी में कुछ शव उतराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गंगा नदी में 10-12 शव उतराते देखे गए थे। ऐसा लगता है कि ये शव पांच-सात दिन से नदी में हैं। हमारे यहां शव को नदी में बहाने की प्रथा नहीं है हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। शव वाराणसी प्रयागराज या किसी अन्य स्थान से आए हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम घाट के आसपास के इलाकों के पास तैनात अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा न हो। गंगा नदी के किनारे बसे कई अन्य गांवों के लोग जो गंगा के जल का इस्तेमाल करते हैं वह भी यहां शवों का अंबार देख भयभीत हो गए हैं। निश्चित रूप से इस तरह के स्थिति सामने आने के बाद अब दूसरे तरह की महामारी जन्म लेगी। गांव के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर कई ऐसे लोग यहां आए जो शव को सीधे गंगा में प्रवाह कर चले गए।

देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में 3.66 लाख नए मरीज, 3754 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर भयानक रूप से जारी है। हालांकि पिछले एक दिन में कुछ राहत मिली है और दैनिक मामले चार लाख से नीचे रहे। मसलन देश में पिछले 24 घंटे में 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,754 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को जारी आंकड़ों पर गौर की जाए तो देश कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, लेकिन लगातार चार दिनों से चार लाख से ज्यादा मामले अब कम हुए हैं। यानि सोमवार को देश में 3,66,161 नए कोरोना मरीज सामने आए और 3,754 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते भयावह माहौल बना हुआ है और

लोगों में भय नजर आ रहा है। इसके कारण ही कोरोना मरीजों के सामने अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,62,575 हो गई है। जबकि 2,46,116 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है।

सक्रिय मामलों का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ- देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ने के कारण अस्पतालों में इलाज करा रहे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 37,45,237 हो गई है, जो अमेरिका के बाद भारत में सबसे अधिकहै। जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या इससे ज्यादा बढ़ने से राहत नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,53,818 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इस प्रकार अब तक देश में 1,86,71,222 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे। इस सप्ताह देश में कुल 27,44,545 मामले सामने आए जिनमें पिछले हफ्ते 26.13 लाख के मुकाबले 5 फीसदी अधिक रहा। पिछले हफ्ते मामलों में 16 फीसदी का उछाल आया था।पिछले सप्ताह देश में 27 हजार से अधिक की मौत हुई और कुल 27.4 लाख मामले दर्ज किए गए। ये किसी भी सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा रहा। इस दौरान मौत का आंकड़ा 15 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ा। पहली बार लगातार तीन दिन के दौरान सीएफआर एक फीसदी रहा। 3 से 9 मई के बीच कुल 27,243 मरीजों ने अपनी जान गंवाई जबकि इससे पहले के सप्ताह में मौत का आंकड़ा 23,781 था।

17 करोड़ लोगों का टीकाकरण- देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है और अब तक 17 करोड़ से ज्यादा को कोविड वैक्सीन की डोज लगाई है। इस आंकड़े तक पहुंचने में भारत को 113 दिन लगे, जबकि चीन को 119 दिन और अमेरिका को 115 दिन लगे थे। सोमवार सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 17,01,76,603 वैक्सीन की खुराक दी गई हैं। इनमें 95,47,102 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें पहली डोज और 64,71,385 को दूसरी डोज दी गई। इसके अलावा 1,39,72,612 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने पहली और 77,55,283 ने दूसरी खुराक ली। 18 से 44 आयुवर्ग के 20.31 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। पिछले दस दिनों में 3.28 लाख से अधिक मरीज औसतन रोजाना ठीक हो रहे हैं।

कोरोना की वैक्सीन में नहीं होगी कमी

देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए दिन-रात काम कर रही है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए देश में निर्मित दो टीके अभी लगाए जा रहे हैं, जबकि आयातित स्पूतनिक वी टीके भी जल्द कार्य म में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कि देश में रूस द्वारा विकसित की गई कोविड वैक्सीन स्पूतनिक-वी का उत्पादन शुरू होने वाला है। देश में स्पूतनिक-वी वैक्सीन का आयात शुरू हो चुका है और इसकी एक खेप भी आ चुकी है। इस महीने के आखिर तक 30 लाख वैक्सीन और भारत पहुंच जाएंगे। मिशन कोविड सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेनु स्वरूप ने कहा है कि देश में इस वैक्सीन का उत्पादन जुलाई से शुरू हो सकता है।

गरीबों की मदद के बहाने हो रहा धर्मांतरण : विहिप

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व हिन्दू परिषद ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में गरीब लोगों की मदद के बहाने कुछ ईसाई मिशनरी लोग उन्हें ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि ऐसे प्रयास पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में किये जा रहे हैं। संगठन ने इन राज्यों से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

विहिप के शीर्ष नेता डॉक्टर सुरेन्द्र जैन ने सोमवार को कहा कि कोरोना काल में देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थितियां विकट हुई हैं। लोग इनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं विहिप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश में जरूरतमंद लोगों की सूखा राशन, तैयार भोजन और इलाज संबंधी मदद कर रहा है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों का लाभ

उठाते हुए कुछ इसाई संगठन कुछ गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और इन राज्यों की सरकारों को इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोई कोशिश नहीं करती हैं, तो संगठन इसके विरुद्ध जन अभियान छेड़ने के लिए मजबूर होगा।

कोरोना संकट : भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में कोविड-19 संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और दावा किया कि राज्य सरकार प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च कर लोगों को 'गुमराह' कर रही है तथा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर उसने सब कुछ केंद्र के भरोसे छोड़ रखा है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को डिजिटल माध्यम से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सूचना का अधिकार के तहत मिले एक जवाब का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार

2015 से अब तक विज्ञापनों पर 805 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में उसने एक भी नया अस्पताल नहीं खोला। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पर हमला करते हुए पात्रा ने कहा मुख्यमंत्री रोजाना टेलीविजन पर आते हैं और 'झूठ' बोल कर लोगों को 'गुमराह' करते हैं। उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन करते रहे और दावे करते रहे कि लॉकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और लोगों के घरों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। जब आपको लगा कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं तब आपने केंद्र पर सवाल उठाने शुरु किए और फिर बाद में अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने 26 अप्रैल को दावा किया था कि उनकी सरकार 1.34 करोड़ टीकों का आर्डर देगी, जिसकी कीमत तकरीबन 1400 करोड़ रुपये होती है। उन्होंने कहा कि आज वह कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है।

पात्रा ने आरोप लगाया कि टीकाकरण अभियान को समय पर आगे बढ़ाने की जगह दिल्ली सरकार विज्ञापनों में व्यस्त रही और अब ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर वह राजनीति कर रही है। बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कम ही प्रयास किए जबकि चहल ने भी कहा है कि इसके लिए लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने टीकाकरण नीति का किया बचाव

» नीति में नहीं है न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी टीकाकरण नीति को न्यायोचित बताते हुए कहा कि उसकी प्रतिक्रिया और रणनीति पूरी तरह से विशेषज्ञ चिकित्सीय व वैज्ञानिक राय से प्रेरित है जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद कम है और जोर देकर कहा कि देश भर में सभी आयुवर्ग के नागरिकों का मुफ्त टीकाकरण होगा। उसने कहा कि एक कार्यकारी नीति के तौर पर जिस अभूतपूर्व व विशिष्ट परिस्थिति में टीकाकरण अभियान को तैयार किया गया है उसमें कार्यपालिका की समझ पर भरोसा किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने कहा कि एक वैश्विक महामारी में जहां राष्ट्र की प्रतिक्रिया और

रणनीति पूरी तरह से विशेषज्ञ चिकित्सीय और वैज्ञानिक राय से प्रेरित है, किसी भी तरह का अति उत्साही, यद्यपि उचित अर्थ में न्यायिक हस्तक्षेप के अभूतपूर्व व अनापेक्षित परिणाम हो सकते हैं। शीर्ष अदालत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन को लेकर स्वतः संज्ञान से शुरू किये गए मामले में रविवार रात को दायर 218 पन्नों के हलफनामे में केंद्र ने कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है और विशेषज्ञों, राज्य सरकारों तथा टीका उत्पादकों से कई दौर के परामर्श व चर्चा के बाद बनाई गई है, जिसमें इस अदालत के दखल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्तर की महामारी से निपटने के लिये व्यापक जनहित में कार्यपालिका के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार ने हलफनामे में कहा कि यह भी बताया जाता है कि 18 से 44 आयुवर्ग के नागरिकों का मुफ्त टीकाकरण हो रहा है क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने अपनी 18 से 44 आयुवर्ग की आबादी के लिये मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। इसलिये देश में सभी आयुवर्ग के सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के चैनल से यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास दोनों टीकों की कितनी खुराक उपलब्ध हैं जिससे वे प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान कर सकें। हलफनामे में कहा गया कि बेहद सम्मानजनक तरीके से यह बताया जाता है कि ऐसे गंभीर व अभूतपूर्व संकट जिसका देश मुकाबला कर रहा है, ऐसे में सरकार के कार्यकारी कामकाज के उद्देश्य से व्यापक हित में नीति बनाने के लिये काम की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अभूतपूर्व व विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर यह टीकाकरण अभियान एक कार्यपालिका नीति के तौर पर तैयार किया गया है जिसमें कार्यपालिका की बुद्धि पर भरोसा किया जाना चाहिए।

अगले तीन दिनों में राज्यों को मिलेंगी टीके की नौ लाख खुराके : केन्द्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के पास एक करोड़ से अधिक कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक मौजूद है और अगले तीन दिनों में उन्हें अतिरिक्त नौ लाख से अधिक खुराके दी जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि केन्द्र ने अभी तक राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 रोधी टीकों की 17,93,57,860 खुराकें मुफ्त में दी है। इनमें से बर्बाद हुई खुराकों सहित कुल 16,89,27,797 को इस्तेमाल किया जा चुका है।मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के पास अब भी एक करोड़ से अधिक 1,04,30,063 खुराकें लगाने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा जिन राज्यों का कहना है कि खपत की तुलना में आपूर्ति कम है, उन्होंने सशस्त्र बलों को मुहैया कराए गए टीकों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा, टीकों की नौ लाख से अधिक 9,24,910 अतिरिक्त खुराके अगले तीन दिनों में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को मुहैया कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार के वैश्विक महामारी के नियंत्रण एवं प्रबंधन की पांच सूत्रीय रणनीति का टीकाकरण एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें जांच, संक्रमितों का पता लगाना, उपचार और कोविड से निपटने के दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल है।

कोरोना संकट के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में किसा प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना काल के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को मोदी सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और अक्षमता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

यहां सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की आयोजित बैठक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर चर्चा हुई। वहीं हाल में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकरा भी मंथन किया गया। बैठक में पारित किये गये एक प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार की यह वैज्ञानिक सलाह में इच्छाशक्ति की अवहेलना, महामारी पर

जीत की इसकी समयपूर्व घोषणा और चेतावनी के बावजूद पहले योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। चेतावनी सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ही नहीं, बल्कि संसद की स्थायी कमेटी ने दी थी।% प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएम को अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। पार्टी ने कोरोना पर पारित प्रस्ताव में देश में वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार कठिन तथ्यों से इनकार करती रही। यह भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले महीने पीएम मोदी को एक पत्र में टीके की सप्लाई और ज्यादा लोगों को टीका लगाने के तरीके सुझाए थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा अशोभनीय तरीके से जवाब दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि कोरोना से होने वाली मौतों का डेटा गलत है और कई मौतों को शामिल नहीं किया गया। यह समय चुनौती का सामना करने का है, नाकि मरने वालों की संख्या को कम करने और संक्रमण के आंकड़ों को गलत दिखाने का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मानना है कि यह राष्ट्रीय एकता, उद्देश्य और संकल्प की एक अटूट भावना दिखाने का समय है। प्रधानमंत्री को अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

फिर टाला कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव- सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का एलान कर दिया था, बैठक में कोरोना महामारी के कारण 23 जून को अध्यक्ष के पद का चुनाव करने का फैसला किया गया था, हालांकि महामारी के चलते इस एक बार फिर टाल दिया गया है।

चुनाव नतीजों पर निराशा जताना काफी नहीं- सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हम अगर कहें कि चुनाव नतीजों से काफी निराश हैं तो ये भी काफी नहीं होगा। चुनाव नतीजों पर मंथन करने के लिए मैं एक छोटा समूह बनाने पर जोर दे रही हूं और उम्मीद है कि जल्द ही एक रिपोर्ट के साथ हम दोबारा बैठक करेंगे।

चुनावी हार के कारणों का लगाएंगे पता- कांग्रेस ने चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए अगले 48 घंटे के भीतर एक समूह गठित करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिंता प्रकट करते हुए सोमवार को कहा कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि कांग्रेस में चीजों को दुरुस्त करना होगा।

उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की डिजिटल बैठक में यह प्रस्ताव किया कि चुनावी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक समूह का गठन किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि अगले 48 घंटे के भीतर इस समूह का गठन कर दिया जाएगा और यह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा। एक सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस समूह की रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।